इलेक्ट्रॉनिकी उपभोक्ता उत्पादों को लाइसेंस मुक्त करना

1739. **श्री पराग चालिहा:**
श्री शिवचरण सिंह:

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इलेक्ट्रॉनिकी उपभोक्ता उत्पादों को लाइसेंस मुक्त करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है;

(ख) क्या अन्य वर्गों के उत्पादों को भी इस व्यवस्था के अंतर्गत लाया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोलि मारन): (क) सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश तथा प्रौद्योगिकी संबंधी निर्णय लेने में उद्यमियों को और अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने की दृष्टि से मनोरंजन संबंधी इलैक्ट्रॉनिक उद्योग को लाइसेंसमुक्त कर दिया है जो अपेक्षाकृत अधिक औद्योगिक विकास व रोजगार में योगदान देगा।

(ख) से (घ) इस समय, अनिवार्य लाइसेंसीकरण के अधीन 14 उद्योगों की एक छोटी सूची है। अनिवार्य लाइसेंसीकरण के अधीन सूची की समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है।

औद्योगिक रुग्णता के कारण

1740. **श्री अजीत जोगी:** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक रुग्णता अर्थव्यवस्था में आधारभूत ढांचागत परिवर्तन का परिणाम है और यह मुख्यतः लोगों द्वारा पैदा किए गए कारणों से है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोलि मारन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) तथापि, भारतीय सांख्यकीय संस्थान द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुसार, खराब वित्तीय संरचना तथा/या उत्पादन के घटकों का पुराने समय से ही अकुशल उपयोग तथा/या घटिया विपणन स्थिति आदि से ही औद्योगिक रुग्णता उत्पन्न होती है। उनके अनुसार बी आई एफ आर के पास पंजीकृत रुग्ण फर्मों तथा स्वस्थ्य कम्पनियों के मध्य ब्याज लागत तथा मजूदरी लागत में प्रमुख अन्तर होता है। गैर बी आई एफ आर फर्मों की अनुप्रीतिक तुलना में बी आई एफ आर कम्पनियों की कुल देनदारी इक्यूटी तथा ऋण इक्यूटी सदैव उच्चतर थी। अध्ययन के अनुसार एक ऐसा सूचना आधार सृजित करने की आवश्यकता पर सुझाव दिया गया है जो व्यक्तिगत क्षमताओं और उनके सहयोग दोनों में बड़े ऋण दाताओं की ऋण योग्यता को अभिव्यक्त कर सके। इसके संदर्भ में सूचना ब्यूरो का जो भी मामले हों को निपटाने के लिए सामयिक आर्बिट्रेटर और फास्ट्रेक फेसीलेटर बनाने के लिए तथा इसके संदर्भित मामलों को निपटाने के लिए प्रांसगिक मध्यस्थ और फास्टट्रेक सहयोगकर्ता बनाने हेतु दोषी उधार फर्मों और बी आई एफ आर को सुरक्षित ऋणदाताओं से निगमित संगठन तथा औद्योगिक उत्तरदायित्वों का अंतरण करना है। अध्ययन ने कम्पनियों को वित्तीय पुनर्संरचना का सुझाव दिया है जैसे भूमि बिक्री द्वारा निगमित पुनर्संगठन और इक्यूटी के रूप में कर्ज में बदलना।

वनिता आश्रमों और स्त्री विकास गृहों को वित्तीय सहायता

1741. **श्री चीमनभाई हसीभाई शुक्ला:** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 अप्रैल, 1996 से 31 अक्तूबर, 1996 तक की अवधि के दौरान राज्यवार कितने वनिता आश्रमों और स्त्री विकास गृहों (महिला उत्थान केन्द्र) को कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) क्या इनमें से कुछ संगठनों द्वारा इस धनराशि का दुरुपयोग किए जाने के संबंध में कोई शिकायत मिली है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान गुजरात में किन-किन शहरों में नये वनिता आश्रम और स्त्री विकास गृह खोलने के लिए वित्तीय सहायता दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनकी प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम क्या-क्या हैं तथा महिलाओं के प्रवेश के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी

Joint venture with Hongkong based Consolidated Electric Power Asia Limited

1742. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether Government have asked Hongkong based Consolidated Electric Power Asia Limited (CEPA) to float a separate joint venture to develop the captive coal mine and put up a washery at the pit head in Orissa, as reported in the Hindustan Times dated 21st November, 1996;

(b) if so, the details thereof, indicating the proposed total installed capacity of the project and CEPA's minimum controlling stake; and

(c) whether CEPA has finalised details for fuel linkage in consultation with CIL indicating quantity of coal likely to be supplied for the Hirma plant in addition to the million tonnes being supplied by CIL to plant?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) to (c) M/s. Consolidated Electric Power Asia Ltd. (CEPA) are proposing to set up a 6×660 MW power station at Hirma in Orissa. Their requirement of coal is 18 mtpa. Coal India has agreed to a long term coal linkage of 12 mtpa for the above power station. Discussion on Fuel Supply Agreement (FSA) have started between CIL and power company., For the balance 6 mtpa of coal requirement the power Company nas requested for identification of a captive mining block. The proposal is under consideration of the Screening Committee of Ministry of Coal in consultation with CIL. Operation of the captive mining block by a joint venture company is an option available to the promoters.

खुली और लेवी चीनी के अनुपात में परिवर्तन

1743. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी**: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खुली और लेवी चीनी के अनुपात में परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार किया है;

(ख) चीनी का क्या सीजन प्रारंभ होने के पहले पिछले तीन वर्षों में चीनी का भंडार कितना रहा है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान गन्ने के संबंध में मिलों पर बकाया राशि कितनी है; और

(घ) चीनी का बफर स्टाक बढ़ाने के लिए क्या नीति बनाई जा रही है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) फिलहाल, आंशिक नियंत्रण की चीनी नीति में दिए गए मुक्त बिक्री और लेवी चीनी के वर्तमान 60:40 के अनुपात में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अगला चीनी मौसम शुरू होने से पहले चीनी का स्टाक निम्नानुसार था:—

चीनी मौसम	निम्न तारीख को	स्टाक लाख टन में
1993-94	30.9.1994	21.93
1994-95	30.9.1995	54.95
1995-96	30.9.1996	लगभग 81.00

(ग) 30 सितम्बर को स्थिति के अनुसार पिछले तीन चीनी मौसमों के लिए गन्ने के कुल देय